अमेरिका-भारत संबंध

व्यापक, रणनीतिक, विविधतापूर्ण और विकासशील

लॉरिडा कीज़ लौंग

राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड से इंटरव्यू

पॉलिन अमेरिका © ए. पी. - डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था में नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से कुछ पहले सभी अमेरिकी राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य और बहुत से नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने इस्तीफे सौंप कर नई शासकीय मंडली के अपना कार्यभार संभालने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। भारत में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करने के ठीक पांच बरस बाद राजदूत डेविड सी.मल्फ़र्ड ने 20 जनवरी से प्रभावी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और असाधारण रूप से, राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन ने उनसे अपने पद पर कुछ समय बने रहने को कहा है जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकी प्रशासन भारत से अपने सम्बन्धों को कितनी गम्भीरता से लेता है। इस बीच राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड लोगों से विदा ले रहे हैं, स्पैन के लिए इस अंतिम साक्षात्कार में वह अपनी पत्नी जीनी के साथ भारत में बिताए पांच बरसों के बारे में बता रहे हैं।

भारत और अमेरिका के सम्बन्धों को और मज़बूत बनाने की दृष्टि से किस क्षेत्र में और काम किए जाने की आवश्यकता है?

हाल तक मुझे लगता रहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष वह क्षेत्र है जो बाकी क्षेत्रों में सहयोग की तुलना में उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहा, इसमें अधिक गहन सहयोग की आवश्यकता है। और इसके अनेक कारणों में से एक है इस क्षेत्र की प्रकृति और जटिलता, जिसमें गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान और सम्भवत: साझे अभियानों में सहयोग भी शामिल हैं। और मैं सोचता हूं कि कुछ हद तक इस आदान-प्रदान और सहयोग में देरी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों के कुछ विशिष्ट जटिलताकारी पक्षों के कारण हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच परम्परागत मतभेदों का शायद समय के साथ सहयोग के स्तर को कमज़ोर करने वाला प्रभाव पड़ा।

लेकिन पिछले 18 महीनों में हम सचमुच कुछ प्रगति होती देख पाए हैं और मैं समझता हूं कि हाल में भारत में और विशेष रूप से मुम्बई में हुए हमलों के बाद अब हमारे दो लोकतंत्रों के बीच सहयोग के स्तर को उस स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट दिख रही है, जहां यह होनी चाहिए।

हां इन हमलों के बाद मुम्बइ में एफबीआई दल की उपस्थिति दोनों पक्षों के लिए एक बेहद सकारात्मक अनुभव रहा- इस टीम ने वास्तविक योगदान किया, बहुत अच्छी तरह काम किया और उसकी तारीफ भी हुई है। इस पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, उसे एक सकारात्मक ढंग से देखा और स्वीकार किया गया और मुझे लगता है इससे हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग बन पाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपनी आतंकवाद रोकथाम क्षमता में काफी सुधार लाना है। अमेरिका ने 9/11 के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं झेला क्योंकि हमने अपनी आतंकवाद रोकथाम क्षमता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत के साथ सहयोग करते हुए हम दोनों पक्ष इन अनुभवों से काफी लाभ पा सकते हैं।

लेकिन भारतीय अब भी इस मुद्दे पर चिन्ता व्यक्त करते हैं कि अमेरिका क्या सचमुच पाकिस्तान पर अपनी ओर से कार्रवाई के लिए प्रयास कर रहा है।

भारत की ही तरह पाकिस्तान भी सम्प्रभु राष्ट्र है। और मुम्बई कांड के बाद से अमेरिका ने विदेशमंत्री और अन्य पदाधिकारियों की यात्रा के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम यहां जो हुआ उसे लेकर बहुत गम्भीर हैं और हम पाकिस्तान पर मामले की तह में जाने का दबाव बनाए हुए हैं... और यही बात हमने पाकिस्तान में भी कही है। हमें याद रखना चाहिए कि इस हमले में छह अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और भारत के साथ सहयोग के अलावा भी हमारे कानून के अंतर्गत हमारा एक कर्तव्य है- इस तरह की घटनाओं की तह तक जाना।

2004 में आपके आगमन के बाद से अमेरिका-भारत सम्बन्धों में कौन से महत्वपूर्ण विकास हुए हैं?

हमने सम्बन्धों की विविधता को जबर्दस्त ढंग से बढ़ते देखा है, इस हद तक कि इराक के अलावा भारत स्थित अमेरिकी मिशन तमाम अमेरिकी मिशनों में सब से बड़ा है। अमेरिकी शासन की करीब 25 अलग-अलग एजेंसियां और विभागों का प्रतिनिधित्व यहां हो रहा है, और इससे भारत से हमारे संवाद की विविधता के बारे में पता चलता है।

सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि क्या रही?

नागरिक परमाणु समझौता जिसे सम्बन्धों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया की नींव जैसा माना गया। अनेक बाधाओं और जटिलताओं के बावजूद साढ़े तीन बरस से अधिक चली प्रक्रिया के बाद यह पूरा हुआ और इसके परिणामस्वरूप नागरिक परमाणु प्रौद्यौगिकी के संसार में भारत की वापसी हो पाई है।

इसके अलावा अन्य सन्तोषप्रद क्षण?

क्योंकि शिक्षा और भारत में शैक्षिक संस्थानों के विकास की क्षमता में मेरी काफी रुचि है, इसलिए मुझे खासतौर पर इस बात से बहुत खुशी हुई कि हम फुलब्राइट समझौते का नवीकरण और इसे विस्तार दे पाए। हम भारत को इस कार्यक्रम को हमारे ही बराबर वित्त समर्थन देने को, लाभार्थियों की संख्या दुगनी करने को, और इस बहुत ही शानदार ब्रांड फुलब्राइट के भावी विस्तार के लिए निजी संसाधन तलाशने के लिए सहमत कर पाए - इस सब पर मुझे गर्व है।

रक्षा और सैन्य मामलों में सहयोग कितना बढ़ा?

सैन्य और रक्षा सम्बन्धों में बेहद वृद्धि हुई है। साझा सैन्य अभ्यासों की संख्या काफी बढ़ी, हम बड़े रक्षा सम्बन्धी सौदे करने लगे हैं। एकदम हाल ही में हमने निगरानी विमानों का 2.2 अरब डॉलर का ठेका किया है। भारत अपने आपूर्ति आधार की विविधता बढ़ाना चाहता है। वह संसार की सर्वोच्च प्रौद्योगिकियां चाहता है। अमेरिका के पास वे सैन्य संसाधन हैं। और उन्हें इन सौदों में पूरी तरह पारदर्शी जवाबदेही मिलती है, किसी छिपे तौरतरीके या भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं।

भारतीयों को अमेरिकी वीज़ा प्राप्त होने की प्रक्रिया में काफी बदलाव हुआ है। यह कैसे हो पाया?

सार्वजनिक कूटनीति के दृष्टिकोण से हमारा तथाकथित वीज़ा अभियान शायद सबसे अधिक संतोषजनक रहा। वर्ष 2006 के बीच के महीनों तक हालात यह थे कि भारतीय नागरिकों को वीज़ा साक्षात्कार के लिए 187 दिन तक इन्तज़ार करना पड़ रहा था। हमने मिशन के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया और तय किया कि हम इस समस्या का हल करेंगे। और कुछ ही महीनों में हम भारत में हर कहीं वीज़ा साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा अवधि केवल छह दिन तक ले आए। और इस प्रसंग में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह है कि तब से कुछ अपवादों को छोड़कर हम भारत में अधिकांश जगहों पर, अधिकांश समय इन्तज़ार की अवधि को 14 दिन से कम रख पाए हैं।

हमें लोगों से तमाम तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं ... यह शायद भारत में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए हम जो करते हैं उस पर प्राप्त सर्वाधिक कूटनीतिक प्रतिफल है।

और हैदराबाद में नया अमेरिकी कांसुलेट शुरू हुआ है।

जैसा कि मुझे बताया गया है, यह पिछले 20 बरसों में खुला अमेरिका का सभी सेवाओं वाला पहला कांसुलेट है। इससे पहले ऐसा कांसुलेट उत्तर-पूर्वी चीन में खुला था। मुझे बताया गया है कि इस कांसुलेट के खुलने से हर वर्ष भारतीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली हैदराबाद से चेन्नई की 100,000 यात्राएं बचेंगी- उन्हें विमान के टिकट नहीं लेने होंगे, यात्रा पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, रातभर रुकना नहीं पड़ेगा, न ही भोजन आदि पर खर्च करना होगा क्योंकि यह प्रक्रिया वहीं पूरी हो जाएगी। यह वास्तविक सुविधा है।

एक अलग राजनीतिक दल के राष्ट्रपति के नए प्रशासन के अन्तर्गत काम करने की परिवर्तन प्रक्रिया क्या है?

राजनीतिक नियुक्तियों वाले लोगों को नए प्रशासन के आगमन से पहले अपने पदों से त्यागपत्र देना होता है ताकि नए प्रशासन के पास प्रशासन के निचले स्तर तक परिवर्तन का विशेषाधिकार और क्षमता हो। इसका अर्थ है कि नई सरकार बहुत जल्द ही अपना रूप तय कर लेती है क्योंकि पूरे प्रशासन में नेतृत्व के काफी क्षेत्रों में वह परिवर्तन कर पाती है। इससे ताज़ा शुरुआत और नए लोगों को आने और तुरंत प्रभावी होने का मौका मिलता है। यह स्पष्ट करता है कि अमेरिका खुद को नए ढांचे में इतनी जल्दी कैसे ढाल लेता है और अपेक्षाकृत कम अवधि के भीतर ही खुद को बदल लेता है।

लेकिन क्या इससे भारतीयों की चिंता नहीं बढ़ेगी कि ऐसे व्यापक बदलाव से संबंध और नीतियां भी प्रभावित हो सकती हैं?

मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ हमारे संबंधों के कदम अब उस तरह पीछे लौटेंगे जैसे कि पहले कभी-कभी लौटे हैं। मुझे लगता है कि इन सम्बन्धों की दिशा और संवेग स्थापित हो चुके हैं और इन्हें बनाए रखा जाएगा। मुझे तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखता जिसके कारण कोई बड़ा उलटफेर हो।

नीचे: अमेरिकी दूतावास के भवन के 50 साल पूरे होने के मौके पर 5 जनवरी को आयोजित समारोह में राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ।

नीचे दाएं: भारत और अमेरिका में आतंकवाद के शिकार बने लोगों की याद में मुंबई में आयोजित समारोह में राजदूत और उनकी पत्नी जीनी मुंबई में 2006 के ट्रेन विस्फोट में सुरक्षित बचे रहे इब्राहिम जॉर्ज से बातचीत करते हुए।

प्रेमेश मल्हार

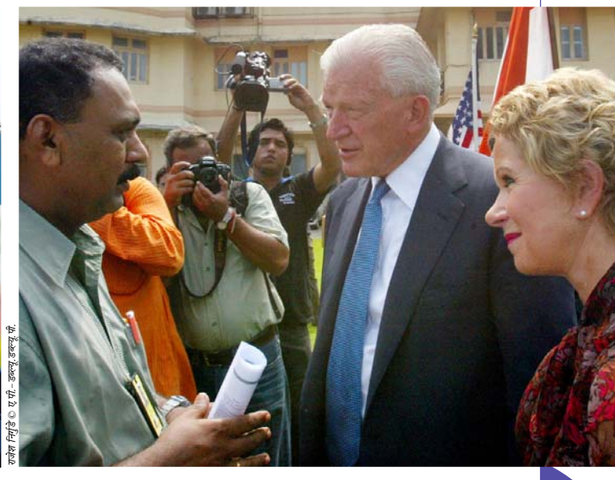

राजेश निगुंडे © ए. पी. - डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.